



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 290]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 28, 2006/पौष 7, 1928

No. 290]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 28, 2006/PAUSA 7, 1928

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2006

(निर्णायक समीक्षा)

विषय: अमरीका, जापान, ईयू एवं सिंगापुर के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित 3000-4000 आण्विक भार के फ्लैक्सिबल स्लेव स्टॉक पॉलीओल (एफएसपी) के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क से संबंधित निर्णायक समीक्षा की शुरुआत।

सं. 15/25/2006-डीजीएडी.—यतः वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर शुल्क अथवा अतिरिक्त शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतदपश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) ने 19 सितम्बर, 2002 की अधिसूचना संख्या 41/1/2001-डीजीएडी तथा 30 सितम्बर, 2002 के शुद्धिपत्र के तहत अमरीका, जापान, ईयू एवं सिंगापुर (जिन्हें आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित फ्लैक्सिबल स्लेव स्टॉक पॉलीओल (जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयात पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करते हुए अपने अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित किए थे।

और यतः संबद्ध वस्तु पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क 31 अक्टूबर, 2002 की सीमाशुल्क अधिसूचना के तहत लगाया गया था।

2. विचाराधीन उत्पाद

मूल जांच और इस वर्तमान समीक्षा में शामिल उत्पाद फ्लैक्सिबल स्लेव स्टॉक पॉलीओल है जो कि एक पॉलीमर होता है। यह प्रोपीलीन ऑक्साइड तथा एथीलीन ऑक्साइड के ट्रायॉल चैन स्टार्टर के साथ पॉलीमेराइजेशन द्वारा विनिर्मित आण्विक भार 3000-4000 का स्पष्ट विस्कस द्रव होता है। यह पॉलीइथर है और इसकी दुलाई टैंकरों में की जाती है अथवा इस्पात के ड्रमों में भंडारण किया जाता है।

फ्लैक्सिबल स्लेव स्टॉक पॉलीओल सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 39 के अंतर्गत और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वर्गीकरण के अनुसार 3907.20 के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है तथा वर्तमान जांच के कार्यक्षेत्र पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है।

3. जांच की शुरुआत

सीमा शुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 और उसके अंतर्गत बनाए गए पाटनरोधी नियमों के तहत प्राधिकारी से पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की जरूरत की समय-समय पर समीक्षा करने की अपेक्षा की जाती है। निर्दिष्ट प्राधिकारी का यह मानना है कि संस्तुत पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 की धारा 9क(5) के उपबंध के अंतर्गत इस चरण पर उचित रहेगी।

मै. मनाली पेट्रोकेमिकल्स लि., चेन्नई ने संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की जरूरत की पुष्टि करते हुए एक आवेदन दायर किया है और उपर्युक्त अधिसूचनाओं के तहत संबद्ध वस्तु पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को आगे और पाँच वर्षों की अवधि तक जारी रखने और उसमें वृद्धि करने का अनुरोध किया है।

4. शामिल देश

वर्तमान जांच में शामिल देश अमरीका, जापान, यूरोपीय संघ और सिंगापुर हैं।

5. समीक्षा के आधार

आवेदक ने बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा लाभ मार्जिन हेतु वृद्धि करने के बाद उत्पादन की परिकलित लागत के आधार पर संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य का दावा किया है। निर्यात कीमत का दावा ऑनलाइन टेलिकॉम नेटवर्क सर्विसेज, मुम्बई से आवेदक को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर किया गया है। समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, निर्यात के देश में अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन हैंडलिंग और पत्तन प्रभारों, कमीशन आदि के लिए कीमत समायोजनों का दावा किया गया है ताकि निवल निर्यात कीमत निकाली जा सके।

जांच शुरुआत के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने प्रथम दृष्टया उत्पादन की परिकलित लागत तथा निर्यात कीमत से संबंधित सूचना के आधार पर संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य, याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुसार संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के लिए दावा किए गए समायोजनों पर विचार किया है।

यह अनुरोध लागू पाटनरोधी शुल्क को जारी रखना और उसमें वृद्धि करने के बारे में है और इसका आधार यह है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद पाटन जारी है। इसके अलावा, आवेदक ने आरोप लगाया है कि क्षति का निर्धारण मुख्यतः पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी के कारण हुआ है और शुल्क निरस्त किए जाने से संबद्ध देशों से फटित कीमतों पर पर्याप्त आयात पुनः शुरू हो जाएंगे जिससे घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होगी। आवेदक ने उस स्थिति में आगे और क्षतिकारक पाटन की संभावना का भी आरोप लगाया है यदि पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर दिया जाता है क्योंकि वर्तमान आयातों में संबद्ध देश में अप्रयुक्त क्षमता होने के कारण वृद्धि होने की संभावना है।

6. प्रक्रिया

सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 और पाटनरोधी नियमावली के अनुसार दिनांक 19-9-2002 की अधिसूचना सं. 41/1/2001-डीजीएडी तथा 30-9-2002 के शुद्धि-पत्र के तहत अधिसूचित अंतिम जांच परिणामों और 31-10-2002 की अधिसूचना द्वारा लगाए गए अंतिम शुल्क की समीक्षा करने का निर्णय लेने के बाद प्राधिकारी इस बात की समीक्षा करने के लिए एतद्वारा जांच शुरू करते हैं कि क्या पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने से अमरीका, जापान, यूरोपीय संघ और सिंगापुर के मूल के या वहां से निर्यातित फ्लैक्सिबल स्लेबस्टॉक मॉलीओल के आयातों का पाटन और उससे होने वाली क्षति जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

इस समीक्षा में 21-9-2001 की अधिसूचना सं. 41/1/2001-डीजीएडी के सभी पहलू शामिल हैं। मै. मनाली पेट्रोकेमिकल्स लि. ने मूल जांच में भी घरेलू उद्योग की ओर से प्रतिनिधित्व किया है। प्राधिकारी का प्रस्ताव उपर्युक्त नियमों के अनुसार आवेदक, जिसका भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन का 100 प्रतिशत हिस्सा है, को घरेलू उद्योग के रूप में मानने का है।

7. जांच अवधि

वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच अवधि 1 अप्रैल, 2005 से 30 जून, 2006 (15 माह) है। तथापि, क्षति विश्लेषण में वर्ष 2002-2003 से जांच अवधि तक के वर्ष शामिल होंगे।

8. सूचना प्रस्तुत करना

संबद्ध देश के निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों/उच्चायोगों के जरिए उनकी सरकार/प्रतिनिधियों, भारत में संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए और निम्नलिखित को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है :

निर्दिष्ट प्राधिकारी,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
वाणिज्य विभाग
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी)
कमरा सं. 240, उद्योग भवन,
नई दिल्ली-110011

कोई अन्य हितबद्ध पार्टी भी जांच से संगत अपने अनुरोध नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से प्रस्तुत कर सकती है।

9. समय सीमा

वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई हेतु कोई अनुरोध लिखित में भेज जाए जो प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस समीक्षा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिन) से पूर्व पहुँच जाने चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त हुई सूचना अधूरी है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी पाटनरोधी नियमों के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

10. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश रखे हुए हैं। यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है अथवा उचित अवधि के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

डॉ. क्रिस्टी फेर्नांडेज, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2006

(SUNSET REVIEW)

Subject : Initiation of Sunset Review on - anti-dumping duty imposed on imports of Flexible Slabstock Polyol (FSP) of molecular weight 3000-4000 originating in or exported from USA, Japan, EU & Singapore.

No. 15/25/2006-DGAD.—Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as AD Rules), *vide* Notification Number 41/1/2001-DGAD dated 19th September 2002, and corrigendum dated 30th September 2002, the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) notified its final findings recommending definitive antidumping duty on import of Flexible slabstock polyol (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from the United States of America, Japan, European Union & Singapore (hereinafter referred to as subject countries).

And whereas definitive antidumping duty was imposed on the subject goods *vide* Customs Notification dated 31st October 2002.

2. Product Under Consideration

The product involved in the original investigation and this current review is Flexible slabstock polyol, which is a polymer. It is a clear viscous liquid of molecular weight 3000-4000, manufactured by polymerization of propylene oxide and ethylene oxide with a triol chain starter. It is a polyether and transported in tankers or stored in steel drums.

Flexible slabstock polyol is classified under Chapter 39 of the Customs Tariff Act, 1975 and further under 3907.20 as per International Trade Classification. The classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

3. Initiation

The Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and the AD Rules made there under require the Authority to review from time to time the need for continuance of anti-dumping duty. The Designated Authority considers that the sunset review of the anti-dumping duty recommended would be appropriate at this stage under the provision of section 9A (5) of the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 as amended.

M/s. Manali Petrochemicals Ltd., Chennai has filed an application substantiating the need for sunset review of the anti-dumping duty imposed on the subject goods originating in or exported from the subject countries and have requested for continuation and enhancement of the anti-dumping duty imposed on subject goods under the above mentioned notifications for a further period of 5 years.

4. Country(ies) Involved :

The countries involved in the present investigations are the USA, Japan, European Union & Singapore.

5. Grounds for Review -

The applicant has claimed normal value of subject goods in the subject countries on the basis of constructed cost of production after addition for selling, general and administrative expenses and profit margin. The export price has been claimed on the basis of data provided by the applicant from Online Telecom Network Services, Mumbai. Price adjustments have been claimed on account of ocean freight, marine insurance, inland transportation in the country of exports, port handling and port charges, commissions etc. to arrive at the net export price.

For the purpose of initiation, the Authority has *prima facie*, considered the normal value of the subject goods in the subject country on the basis of constructed cost of production and information on the export price, the adjustments claimed for the subject goods from the subject country as made available by the petitioner.

The request is for continuation and enhancement of the anti-dumping duties in force and is based on the grounds that dumping has continued in spite of imposition of anti-dumping duty on import of the subject goods from the subject country. In addition the applicant alleges that the removal of injury was mainly due to the existence of anti-dumping duty and revocation of duty would lead to recurrence of substantial imports at dumped prices from subject countries and would be likely to lead to a recurrence of injury to the domestic industry. The applicant has further alleged likelihood of further injurious dumping if the anti-dumping duty be allowed to lapse, as the current imports may be likely to increase due to existence of unused capacity in the subject country.

6. Procedure :

Having decided to review the final findings notified vide No. 41/1/2001-DGAD dated 19-9-2002 and corrigendum of 30-9-2002 and final duty imposed by Notification dated 31-10-2002, the Authority hereby initiates investigations to review whether cessation of anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury on imports of Flexible slabstock polyol originating in or exported from USA, Japan, European Union & Singapore, in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and AD Rules.

The review covers all aspects of Notification No.41/1/2001-DGAD dated 21-9-2001. M/s. Manali Petrochemicals Ltd., have represented on behalf of the domestic industry in the original investigations also. The Authority proposes to consider the applicants, who constitute 100% of the production of the subject goods in India, as domestic industry in accordance with the Rules *supra*.

7. Period of Investigation :

The period of investigation (POI) for the purpose of the present review is 1st April, 2005 to 30th June, 2006 (15 months). However, injury analysis shall cover the years from 2002-03 to the POI.

8. Submission of Information :

The exporters in the subject country, their government through their Embassies/High Commissions in India/representatives, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the :

**The Designated Authority,
Ministry of Commerce and Industry,
Department of Commerce,
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties, (DGAD),
Room No. 240, Udyog Bhavan,
New Delhi-110011**

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

9. Time Limit :

Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this review notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.

10. Inspection of Public File :

In terms of Rules 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

Dr. CHRISTY FERNANDEZ, Designated Authority

4012 GI/06-2